

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI). (a) and (b). Yes Sir. The external beam is expected to be made available for experiments by the middle of this year

(c) An internal circulating beam was first obtained in June, 1977. But further trials are necessary and will be undertaken in order to maximise the energy of the parties

(d) No, Sir

SHRI RAJ KRISHNA DAWN Without external beam no research can be done and in this sense the machine is not yet operational. It is also notable that though the cyclotron construction began in 1967, twelve years ago, there are still a lot of problems. I would like to know from the hon Prime Minister (a) what is the gestation period of this machine for full operation and (b) when the machine will be commissioned and made operational?

SHRI MORARJI DESAI It is generally agreed that there is a period of about 18 months between the two and the time can be lessened if things are favourable. But there are difficulties in the availability of electricity. Its supply fluctuates off and on and therefore, there is delay.

SHRI RAJ KRISHNA DAWN I would like to know from the hon Prime Minister how the Variable Energy Cyclotron at Salt Lake is up-to-date in this particular field of Nuclear science and how Meghnad Saha Institute of Nuclear Physics at Calcutta is associated with this Project and is it a fact that the project was to be implemented by that Institute first?

SHRI MORARJI DESAI I do not know

MR SPEAKER He wants notice for that

SHRI SAUGATA ROY The main purpose of this Cyclotron was to manufacture radio-active isotopes for medicinal and other purposes. I would

like to know from the hon Prime Minister as to how much money has been spent on this Variable Energy Cyclotron Project till date and what is the value of the radio-active isotopes produced through this cyclotron till date?

SHRI MORARJI DESAI I do not have the figures now and therefore, I cannot give them now

SHRI HARI VISHNU KAMATH Mr Speaker, this question of mine viz, Q No 309 has been transferred to a distant date i.e. 31st of this month. I want to raise a point of order

MR SPEAKER This is question time. After the question hour is over, you can raise that

SHRI HARI VISHNU KAMATH Will you let me raise it after the question is over?

MR SPEAKER Yes let us utilise the full question hour for questions

लघु उद्योग क्षेत्र से कुछ सवों का उत्पादन

* 310 डा० रामजी सिंह क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कुछ वस्तुओं का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिये नियत करने की नीति का पालन करने का है जैसा कि नीति सचची विवरण में कहा गया है,

(ख) क्या धनापाजक और ऋणदाता संस्थाएँ कुल ऋण का केवल 20-25 प्रतिशत ऋण उन उद्योगों का दे रही हैं जिनसे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले करोड़ों लोग लाभ उठा रहे हैं

(ग) यदि हा तो उस दिशा में गत वित्तीय वर्ष में कितना ऋण दिया गया तथा चालू वर्ष में कितना ऋण देने का विचार है, और

(घ) उन उद्योगों का स्वीकार क्या है जिनके लिये छोटे कारखाने खोलने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) :
(क) जी हाँ ।

(ख) लघु उद्योगों को दिया गया संस्थागत ऋण सरकारी क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण का करीब 20 प्रतिशत है ।

(ग) लघु उद्योगों के पास दिसम्बर, 1976 के अन्त में बैंक ऋण की बकाया कुल राशि 1,999 करोड़ रुपये थी । लघु उद्योगों के पास राज्य वित्तीय निगम द्वारा दिए गए सावधिक ऋणों की दिसम्बर, 1976 के अन्त में बकाया राशि 826 करोड़ रुपये थी । वर्ष के दौरान दिए जाने वाले प्रस्तावित ऋण की राशि का अनुमान हम अबस्था में नहीं लगाया जा सकता ।

(घ) सरकार की नीति सभी जीव्य लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की रूढ़ि है ।

डा० रामजी सिंह अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी ने लघु उद्योगों को आरक्षण देने की बात बहुत जगह कही है । 1972-1973 में लघु उद्योगों को जो ऋण दिया गया 645 करोड़ रुपये में बढ़ाकर 1976-77 में 1260 करोड़ हो गया । यानी 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तो क्या लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की जो घोषित नीति है, और चालू वर्ष में उन्होंने आकड़े उपस्थित नहीं किये हैं तो यह 70 प्रतिशत की जा वृद्धि हुई है क्या आप इससे अधिक ऋण देने की क्षमता कर सकेंगे या आपने 70 प्रतिशत में बढ़ाया है, तब समझा जायगा कि आप सचमुच में लघु उद्योगों को आरक्षण द रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस जिस नीति को हम चला रहे हैं उसमें लघु उद्योगों का विकास बड़ी तेजी से कर रहे हैं । राष्ट्रीयकृत और

निजी क्षेत्रों के बैंकों से इस सम्बन्ध में वास्तविक हो चुकी है और लघु उद्योगों को जो भी ऋण की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिये हर प्रकार का इंतजाम किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आयीगी ।

डा० रामजी सिंह हमारे उद्योग मंत्री जी ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के विषय में बहुत जगह कहा है —

“Small Units problems to be studied —Administrative College of India”

उन्होंने कोट्टायम में भी कहा है कि मल्टी नेशनल्स और ट्रांस नेशनल्स में भी लघु उद्योगों को बचायेंगे । मैं उद्योग मंत्री से पूछना चाहूंगा कि लघु उद्योगों को आरक्षण देने के लिये इन्टरस्ट सबसीडी प्लान आप करेंगे और “एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारन्टी कारपोरेशन” की जो पालिसी है, उसको आप बढ़ायेंगे, “स्माल यूनिट्स के लिये लोकल टैक्स” भी माफ करेंगे, और आपने जो वायदा किया है, 180 आइटम लघु उद्योगों में ली है, उसकी सूची भी मीनिंगफुली बढ़ायेंगे, जैसे धोती माडी में जा बड़े-छोटे उद्योग कर रहे हैं” “फ्रीज एट वरन्ट लैबल आफ प्रोडक्शन” करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह सब प्रश्न इसीलिये कर रहा हूँ कि मंत्री महोदय ने कई जगह घोषणा में इसके सम्बन्ध में आश्वासन दिया है । लघु उद्योगों के सम्बन्ध में मैं इसलिये प्रश्न कर रहा हूँ कि इससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा । जो बातें मैंने कही, लघु उद्योगों के अन्दर धोती और माडी के उत्पादन को आप कितना आरक्षण देंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : इन सारे सुझावों पर हम ठीक ढंग से विचार करेंगे और हर प्रकार की महायता देने का काम करेंगे ।

श्री बाबू सिंह : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि 180 चीजें जो लघु उद्योगों में

रिजर्व थीं, उनकी संख्या बढ़ाकर 504 कर दी गई है ।

पहले भी 180 चीजें रिजर्व कर दी गई थीं, लेकिन उनको भी छोटे उद्योगों में बनाने के लिये प्रोत्साहन पही मिल सका, क्योंकि बड़े उद्योग उनको बनाते थे, जैसे बाटा का जूता बनता है । बाटा वाले छोटे उद्योगों में जो जूते बनते हैं, उन्हें सस्ते दाम में खरीदकर अपनी छाप लगा देते हैं । मेरा प्रश्न यह है कि जो आपने 504 चीजें छोटे उद्योगों के लिये रिजर्व की है, क्या उनके बड़े उद्योगों में बन्दे पर पाबन्दी लगायेंगे ताकि छोटे उद्योग पनप सकें और उनको प्रोत्साहन मिल सके ?

श्री जार्ज, कर्नाटिस सारी उद्योग नीति मदन के मामले 23 दिसम्बर को पेश की गई है उसमें यह मत्र स्पष्ट किया गया है ।

SHRI BEDABRATA BARUA Sir, for the last one year the Minister has made a lot of statements not only the Minister, but think the Home Minister as well, that a lot of products will be reserved for the small-scale sector I know very well that nothing has been done in this regard except making the statements. The test of sincerity is whether the Government is prepared to start the production of these items produced by multi-nationals and big industries in the small-scale sector. Where the small-scale industries have been given the right to produce the items alone, I want to know whether the Government would really start the production of those items now produced by large industries and multi-nationals.

SHRI GEORGE FERNANDES: It is not correct to say that nothing has been done apart from expanding the list of reservations. Very serious efforts are now on to see that items reserved for the small-scale sector are produced in the small-scale sector alone. Through the district industries centres that are now going up all over

the country efforts will be made to see that smallscale sector really develops and grows in the rural areas. So far as multinationals or any large organised houses producing items that can be produced in the small-scale sector or that are reserved for the small-scale sector is concerned, phasing them out is going to take some time. These are not matters where one can, by the push of the button, say that whatever is produced today in a large house or in a big factory or in a multinational concern shall be produced in the small-scale sector, and one cannot, by a fireman or dictat, get everything straightaway from the smallscale sector. It is not possible. There are a large number of workers employed in these units. It will take time, but we are discussing with the larger houses (Interruptions) to find out ways and means, and the modalities of phasing out their production. And I hope that the hon. Member of the Opposition who over the years built the multinationals into producing these items will give us a little time to dismantle whatever they have built.

श्री राम बिलास पासवान : हम लोग छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं, लेकिन जैसा कि मंत्री महोदय का मान्य है बड़े बड़े उद्योग-धंधों, हेवी इंडस्ट्रीज की मोनोपनी बनी हुई है। छोटे उद्योग-धंधों के सामने सब से बड़ी प्राबल्य यह है कि वे जो माल तैयार करते हैं उनकी खपत बँसे हो। उनका माल बिक नहीं पाता है। बड़े उद्योग धंधों के पहले से, पिछली गर्वनमेंट के समय से, जो कट्रेक्ट चले आ रहे हैं, उन कट्रेक्ट्स को अभी तोड़ा नहीं गया है। छोटे उद्योग-धंधे जिस सामान को तैयार करते हैं, सरकार उस के लिए मार्केट उपलब्ध नहीं करती है। इसलिए उन के बन्द होने की नीबत आ गई है। मैंने मंत्री महोदय से बरीनी के बारे में खास तौर से कहा था कि वहा पर सैकड़ों इनवैम्पलायड इंजीनियर छोटे-छोटे उद्योग-धंधे बना रहे हैं और कई

प्रकार का सामान तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्षपण के अभाव में उन लघु उद्योगों को बन्द करने की नीबत घा गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि छोटे उद्योग-धंधों के द्वारा जो माल तैयार किए जाते हैं, क्या मंत्री महोदय उनके लिए बाजार उपलब्ध करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डिस : एक तो हमने राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार से भी कहा है कि लघु उद्योगों में जो चीजें बनती हैं, उनको खरीदने की प्रधानता देनी चाहिए। दूसरे, मार्केटिंग का सवाल बड़ा अहम सवाल है। हम जिला उद्योग केन्द्र बना रहे हैं। उनके माध्यम से, और सरकार की अन्य सस्थाओं के माध्यम से, हम इस समस्या को हल करने के काम में लगे हुए हैं।

SHRI VASANT SATHE: In keeping with his declared policy, the Minister knows that the main hurdle in the entire problem is the competition between the consumer goods produced not only by the multinationals but also by the monopoly houses, small scale sector and the cottage industry sector which he wants to encourage. This is the permanent problem. What is the mechanism by which he will ensure supply of raw material to the small scale producer—as also technological know-how, finance and sale of the end-product? Unless these things are done, do what you may, you will not be able to compete with even the tooth-paste or soap or oil produced by the monopoly houses. How does the Minister propose to do that? What is the mechanism? Even in the industrial policy, that mechanism has not been spelt out. Will he tell us what mechanism of marketing and supply he has in mind?

SHRI GEORGE FERNANDES: I mentioned earlier that the district industry centres that are now coming up, are going to be the instruments through which the problems which the small-scale sector faces, are going

to be tackled—right down at the district level. These district industry centres will be equipped to deal with problems of raw materials and of marketing; and we will, if necessary, set up raw material banks. Insofar as marketing is concerned, the existing marketing organizations, both the Central as well as State Governments, are being strengthened. And the district industry centres have been asked to set up whatever apparatus that may be necessary, to market the products of these small-scale units.

SHRI VASANT SATHE: I asked about technological assistance. Will that be given to the district industry centre?

SHRI GEORGE FERNANDES: It will also have a division which will look after research and development, and will provide the necessary inputs in the technological areas also.

श्री नाथूराम निरवा : भारत सरकार छोटे हाथ के बने हुए औजारों का एक कारखाना लगाना चाहती है। राजस्थान सरकार ने यह कारखाना नागौर में लगाने की सिफारिश की है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस प्रश्न पर विचार किस स्टेज पर है ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : उसके लिए मैंने नोटिस चाहिए।

Export of Indian Films to Pakistan

*311. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

SHRI G. M. BANATWALLA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration to export Indian Films to Pakistan through regular channels;

(b) if so, where the matter stands;